

Paper - GS 1 Subject - Modern History

Model Answer

Que Evaluate the role of the Non-Cooperation Movement in India's freedom struggle with a focus on its outcomes.

The Non-Cooperation Movement (1920-1922), spearheaded by Mahatma Gandhi, was a transformative chapter in India's freedom struggle, symbolizing a decisive shift towards mass mobilization against British rule.

Key Features and Role:

- 1. **Mass Mobilization**: For the first time, the movement engaged millions of Indians, including peasants, workers, students, and women, creating a pan-Indian struggle against colonial rule.
- 2. **Economic Resistance**: By boycotting British goods, government schools, courts, and foreign textiles, the movement weakened the economic base of British colonialism and promoted Swadeshi industries.
- 3. **Hindu-Muslim** Unity: The movement aligned with the Khilafat cause, fostering communal harmony and demonstrating the power of united opposition to British policies.
- 4. **Non-Violence**: It emphasized peaceful methods of resistance, demonstrating the moral superiority of non-violence over violent rebellion.

Outcomes and Impact:

- 1. **Political Awakening**: It instilled political awareness among Indians and marked the entry of common people into the freedom struggle.
- 2. **Economic Impact**: Boycotts reduced British imports, sending a strong message of defiance.
- Foundation for Future Movements: The strategies and lessons of the Non-Cooperation
 Movement paved the way for subsequent campaigns like the Civil Disobedience and Quit
 India Movements.
- 4. **Challenge to British Authority**: It shook the legitimacy of British governance in India, as thousands resigned from government jobs and refused titles.

Limitations:

- 1. **Chauri Chaura Incident (1922)**: The outbreak of violence in Chauri Chaura led Gandhi to call off the movement, exposing the difficulty of maintaining non-violence.
- 2. **Limited Rural Impact**: While urban areas saw significant participation, the movement's reach in rural regions remained inconsistent.
- 3. **Unrealized Objectives**: Despite its scale, the movement did not achieve immediate self-rule, leaving some participants disillusioned.

The Non-Cooperation Movement was a watershed moment in India's freedom struggle. It transformed the fight for independence into a mass-based, non-violent campaign, setting the stage for future movements. Its legacy lies in uniting a diverse population against colonial rule and showcasing the power of collective resistance.



भारत के स्वतंत्रता संग्राम में असहयोग आंदोलन की भूमिका का मूल्यांकन करें, इसके परिणामों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए।

महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन (1920-1922) भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक परिवर्तनकारी अध्याय था, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जन-आंदोलन की दिशा में एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक था।

प्रमुख विशेषताएँ एवं भूमिकाः

- जन-आंदोलनः इस आंदोलन में पहली बार किसानों, श्रमिकों, छात्रों और महिलाओं सहित लाखों भारतीयों ने भाग लिया, जिससे औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अखिल भारतीय संघर्ष का प्रारंभ हुआ।
- **आर्थिक प्रतिरोध:** ब्रिटिश उत्पादों, सरकारी स्कूलों, अदालतों और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करके, आंदोलन ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आर्थिक आधार को कमजोर किया और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया।
- हिंदू-मुस्लिम एकताः यह आंदोलन खिलाफत के उद्देश्य से गठित हुआ, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देता था और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ एकजुट विरोध की शक्ति का प्रदर्शन करता था।
- अहिंसाः इसने प्रतिरोध के शांतिपूर्ण तरीकों पर जोर दिया, हिंसक विद्रोह के स्थान पर अहिंसा की नैतिक श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया।

परिणाम एवं प्रभावः

- राजनीतिक जागृति: इसने भारतीयों में राजनीतिक जागरकता पैदा की और आम लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त किया।
- आर्थिक प्रभावः बहिष्कार ने ब्रिटिश आयात को कम कर दिया, जिससे अवज्ञा का एक मजबूत संदेश गया।
- भिवष्य के आंदोलनों की नींवः असहयोग आंदोलन की रणनीतियों और सबक ने सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बाद के अभियानों के लिए मार्ग प्रशस्त किया।
- ब्रिटिश सत्ता को चुनौती: इसने भारत में ब्रिटिश शासन की वैधता को हिलाकर रख दिया, क्योंकि हज़ारों लोगों ने सरकारी नौकरियों से इस्तीफ़ा दे दिया और उपाधियों को अस्वीकार कर दिया।

सीमाएँ

- **चौरी चौरा कांड (1922):** चौरी चौरा में हिंसा भड़कने के कारण गांधीजी को आंदोलन वापस लेना पड़ा।
- सीमित ग्रामीण प्रभावः जबिक शहरी क्षेत्रों में भागीदारी देखी गई, ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन की पहुंच असंगत रही।
- अप्राप्त उद्देश्यः अपने पैमाने के बावजूद, आंदोलन से तत्काल स्वशासन हासिल नहीं हुआ, जिससे कुछ प्रतिभागी निराश हुए।

असहयोग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने स्वतंत्रता की लड़ाई को जन-आधारित, अहिंसक अभियान में बदल दिया, जिसने भविष्य के आंदोलनों के लिए मंच तैयार किया। इसकी विरासत औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक विविध आबादी को एकजुट करने और सामूहिक प्रतिरोध की शक्ति का प्रदर्शन करने में निहित है।



Paper - GS 2 Subject – Polity and Governance

Model Answer

Que. e-governance, as a critical tool of governance, has ushered in effectiveness, transparency and accountability in governments. What inadequacies hamper the enhancement of these features?

E-Governance has emerged as a transformative tool in modern governance by leveraging technology to improve service delivery, ensure transparency, and enhance accountability. Despite its potential, several inadequacies hinder the full realization of these objectives.

Key Features of E-Governance

1. Effectiveness:

- o Streamlined processes and reduced bureaucratic red tape.
- o Faster service delivery, such as Aadhaar-enabled Direct Benefit Transfers (DBTs).
- Use of platforms like e-Shram for managing unorganized labor.

2. Transparency:

- Access to real-time information through portals like RTI Online and Public Financial Management System (PFMS).
- Digitization reduces corruption by minimizing human intervention.

3. Accountability:

- o Real-time monitoring of government schemes via dashboards like PRAGATI.
- o Citizens' grievances can be tracked and resolved through portals like CPGRAMS.

Key Challenges:

1. Digital Divide

- o Inequitable access to technology across rural-urban, gender, and economic lines limits the reach of e-governance initiatives.
- Lack of digital literacy further marginalizes disadvantaged sections from availing egovernance benefits.

2. Infrastructure Constraints

- o Inadequate digital infrastructure, particularly in remote areas, hampers reliable internet connectivity and access to online services.
- Frequent technical glitches and under-maintained servers reduce the efficiency of digital platforms.

3. Cybersecurity and Data Privacy

- O Vulnerabilities in cybersecurity pose risks to sensitive personal and national data.
- Absence of robust data protection laws and frameworks erodes public trust in egovernance systems.

4. Resistance to Change

- Bureaucratic inertia and resistance to adopting technology hinder the smooth implementation of e-governance.
- o Skill gaps among government employees affect the delivery of digital services.

5. Accountability Concerns

- o Over-reliance on technology can sometimes obscure accountability, as identifying responsible individuals in a digital framework becomes challenging.
- Poor grievance redress mechanisms in e-governance platforms deter citizens from seeking resolutions.

To bridge the digital divide, efforts should focus on improving internet accessibility through initiatives like BharatNet and promoting digital literacy. Strengthening security through data protection laws and enhanced cybersecurity is key. Training government officials and fostering innovation will improve public administration. Additionally, simplifying user interfaces, supporting local languages, and improving grievance redress mechanisms will make services more accessible and accountable.



अभिशासन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई-शासन ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेयता का आगाज कर दिया है। कौन-सी अपर्याप्तताएं इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती हैं ?

ई- शासन आधुनिक शासन में एक परिवर्तनकारी उपकरण के रूप में उभरा है, जो सेवा वितरण में सुधार, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है। इसकी क्षमता के बावजूद, कई अपर्याप्तताएँ इन उद्देश्यों की पूर्ण प्राप्ति में बाधा डालती हैं।

ई- शासन की मुख्य विशेषताएं

- प्रभावशीलताः
 - स्व्यवस्थित प्रक्रियाएँ और नौकरशाही की लालफीताशाही में कमी।
 - o तेज़ सेवा वितरण, जैसे कि आधार-सक्षम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)।
 - असंगठित श्रम के प्रबंधन हेतु ई-श्रम जैसे प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग।
- पारदर्शिताः
 - RTI ऑनलाइन और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) जैसे पोर्टलों के माध्यम से समयोचित जानकारी तक पहुंच।
 - मानवीय हस्तक्षेप को कम कर डिजिटलीकरण भ्रष्टाचार को कम करता है।
- उत्तरदायित्वः
 - o प्रगति जैसे डेंशबोर्ड के माध्यम से सरकारी योजनाओं की समयोचित निगरानी की जा सकती है।
 - CPGRAMS जैसे पोर्टल के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों को ट्रैक और हल किया जा सकता है।

प्रमुख चुनौतियाँः

- डिजिटल विभाजन
 - ग्रामीण-शहरी, लैंगिक और आर्थिक आधार पर प्रौद्योगिकी तक असमान पहुंच ई-गवर्नैंस पहलों
 की पहुंच को सीमित करती है।
 - डिजिटल साक्षरता की कमी ई-गवर्नेंस लाभों का फायदा उठाने से वंचित वर्गों को सुभेद्य बनाती
 है।
- अवसंरचना की बाधाएं
 - अपर्याप्त डिजिटल अवसंरचना, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी
 और ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच में बाधा डालते हैं।
 - बार-बार होने वाली तकनीकी गड़बड़ियाँ और अपर्याप्त रखरखाव वाले सर्वर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की दक्षता को कम करते हैं।
- साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता
 - साइबर सुरक्षा में सुभेद्यता संवेदनशील व्यक्तिगत और राष्ट्रीय डेटा के लिए जोखिम पैदा करती हैं।
 - मजबूत डेटा सुरक्षा विधियों और रूपरेखाओं की अनुपस्थिति ई-गवर्नेस प्रणालियों में जनता के विश्वास को कम करती है।
- परिवर्तन का विरोध



- नौकरशाही की जड़ता और प्रौद्योगिकी को अपनाने का प्रतिरोध ई-गवर्नेंस के सुचार कार्यान्वयन में बाधा डालता है।
- सरकारी कर्मचारियों के बीच कौशल अंतराल डिजिटल सेवाओं की डिलीवरी को प्रभावित करता है।
- उत्तरदायित्व संबंधी चिंताएँ
 - प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता कभी-कभी उत्तरदायित्व को अस्पष्ट कर सकती है, क्योंकि
 डिजिटल ढांचे में उत्तरदायी व्यक्तियों की पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
 - ई-गवर्नेंस प्लेटफ़ॉर्म में निम्न स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र नागरिकों को समाधान प्राप्त करने से रोकता है।

डिजिटल विभाजन को पाटने हेतु, भारतनेट जैसी पहलों के माध्यम से इंटरनेट पहुँच में सुधार और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। डेटा सुरक्षा कानूनों और बढ़ी हुई साइबर सुरक्षा के माध्यम से सुरक्षा को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित करना और नवाचार को बढ़ावा देना सार्वजनिक प्रशासन में सुधार करेगा। इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस को सरल बनाना, स्थानीय भाषाओं का समर्थन करना और शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करना सेवाओं को अधिक सुलभ और जवाबदेह बनाएगा।

An Institute For Civil Services